देहरादून (उत्तराखण्ड)
सोमवार 23.02.2026
समय 1830

मुख्य समाचार :–

- उत्तराखंड में 153 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिलेगी। नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत प्रक्रिया पूरी।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार कुंभ–2027 के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत 408 करोड़ 82 लाख रुपए की परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने का केंद्र से अनुरोध किया।
- मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने उत्तराखंड में रोपवे परियोजनाओं के विकास और क्रियान्वयन के संबंध में पहली बोर्ड बैठक की समीक्षा की। कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
- चम्पावत जिले में जनगणना–2027 को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू।

सीएए

नागरिकता संशोधन अधिनियम– सीएए के प्रावधानों के तहत उत्तराखंड में रह रहे 153 हिंदू शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दिए जाने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। केंद्र और राज्य के गृह विभाग की ओर से विस्तृत जांच–पड़ताल के बाद इनके आवेदनों की स्वीकृति से भारतीय नागरिकता दिए जाने का रास्ता साफ हो गया है। स्वीकृत आवेदनों में 147 लोग पाकिस्तान से और 6 लोग अफगानिस्तान से आए हैं। ये सभी 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण लेने वाले आवेदकों की श्रेणी में आते हैं। इनके परिजन पहले से देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में निवासरत हैं, जिसके चलते इन्हें राज्य में आश्रय मिला। वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि सीएए के माध्यम से वर्षों से भारत में रह रहे शरणार्थी परिवारों को न्याय मिला है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार कुंभ–2027 के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत 408 करोड़ 82 लाख रुपए की परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल से अनुरोध किया है। आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जनवरी से अप्रैल, 2027 तक आयोजित होने वाले कुंभ मेले में देश–विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना है। इसके दृष्टिगत गंगा की निर्मलता, स्वच्छता और अविरलता बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के साथ कुंभ की तैयारियों और नमामि गंगे से संबंधित परियोजनाओं पर केंद्रीय मंत्री से विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए 253 करोड़ के प्रस्तावों की स्वीकृति, जल जीवन मिशन के तहत अतिरिक्त राशि जारी करने करने के साथ ही इकबालपुर नहर प्रणाली, कनखल और जगजीतपुर नहर की क्षमता विस्तार का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे असिंचित

भूमि की सिंचाई के लिए 665 क्यूसेक पानी उपलब्ध हो सकेगा, जिससे हरिद्वार जिले के भगवानपुर और लक्सर क्षेत्र को लाभ मिलेगा। परियोजना से लगभग 13 हजार हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलने का अनुमान है। साथ ही क्षेत्र में पेयजल समस्या के समाधान भी होगा। श्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से हरिद्वार कुंभ को दिव्य, भव्य और ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान किया जाएगा तथा गंगा संरक्षण के लक्ष्य को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकेगा।

एआई कार्यशाला

उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशान्त आर्य ने विभागीय कार्यप्रणाली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी ए.आई. के प्रभावी समावेशन को लेकर आज दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। जिला सभागार में आयोजित कार्यशाला के पहले दिन 34 विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों और कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला में विशेषज्ञ विनीत ने एआई तकनीक के माध्यम से कार्यालयी पत्राचार के मसौदे तैयार करना, डेटा संकलन व विश्लेषण, अभिलेख प्रबंधन, जन शिकायतों की निगरानी, रिपोर्टिंग प्रणाली का आधुनिकीकरण, आदि का प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने एआई का उपयोग विभागीय सुरक्षा और आकंड़ों को ध्यान में रखते हुए करने की सलाह दी। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को गहनता से प्रशिक्षण लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एआई तकनीक के उपयोग से जहां प्रशासनिक कार्यों में गति, पारदर्शिता और गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा, वहीं नागरिकों को अधिक प्रभावी और त्वरित सेवाएं भी उपलब्ध होंगी।

रोपवे परियोजनाएं समीक्षा

मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने आज सचिवालय में उत्तराखंड में रोपवे परियोजनाओं के विकास, क्रियान्वयन, संचालन और रख–रखाव से संबंधित विभागों, हितधारकों तथा कंपनियों के साथ पहली बोर्ड बैठक की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने रोपवे परियोजनाओं को प्रदेश की अर्थव्यवस्था, पर्यटन, और समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए इनके कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड पर बनने वाली इन परियोजनाओं के तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक अनुमोदनों सहित सभी औपचारिकताओं को शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया। देहरादून–मसूरी रोपवे परियोजना में हो रही देरी पर मुख्य सचिव ने इसकी प्रगति में तेजी लाने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने जिला प्रशासन, सरकारी निर्माण एजेंसियों, लोक निर्माण विभाग और सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर स्थानीय स्तर पर आने वाली चुनौतियों का समाधान करने की बात भी कही।

जनगणना प्रशिक्षण

चम्पावत जिले में जनगणना–2027 के सफल, पारदर्शी और समयबद्ध क्रियान्वयन को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में आज से तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जनगणना कार्य से जुड़े अधिकारियों को निर्धारित प्रक्रियाओं, तकनीकी व्यवस्थाओं और दायित्वों की विस्तार से जानकारी दी जा रही है। देहरादून से आए सांख्यकीय अनुवेषण व प्रशिक्षक भावेश कुमार धीमान ने बताया कि अधिकारियों को जनगणना संबंधित प्रशिक्षण डिजिटल माध्यम से दिया जा रहा है।

जैविक रंग

चम्पावत जिले में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत गठित महिला समूहों द्वारा इन दिनों विभिन्न स्थानों पर बुरांश, हल्दी, गेंदा, पालक, गुलाब, चुकंदर और मुल्तानी मिट्टी से जैविक रंग बनाए जा रहे हैं। इन रंगों को स्टॉलों के साथ ही ऑनलाइन माध्यम से बेचा जा रहा है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। जिला मुख्यालय के नजदीक विन्डा गांव की एक स्वयं सहायता समूह की महिला लक्ष्मी जोशी ने बताया कि अभी तक उन्होंने ढाई कुन्तल रंग तैयार कर विभिन्न स्टालों और सरस मेले के माध्यम से बिक्री के लिए रखे हैं। गांव की अन्य महिला राधा राणा और कमला बोहरा ने बताया कि वे खाद्य पदार्थों और फूलों से हर्बल गुलाल तैयार कर रही हैं, जो त्वचा के लिए सुरक्षित होने के साथ ही पर्यावरण के अनुकूल भी है।

अतिक्रमण

हरिद्वार की नगर मजिस्ट्रेट कुश्म चौहान की अगुवाई में आज देवपुरा चौक से लेकर रेलवे स्टेशन हरिद्वार तक फुटपाथ पर हुए अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान बस स्टैंड के सामने रेलवे स्टेशन की दीवार से लगती हुई लगभग 80 अस्थाई दुकानें और रेहड़ी–ठेली हटाई गई। नगर मजिस्ट्रेट ने कहा कि शहर में अतिक्रमण वाले फुटपाथों को तत्काल अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। उन्होंने नगर निगम और पुलिस को भी निर्देशित किया कि जिन–जिन स्थलों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, यह सुनिश्चित किया जाए कि वहां फिर से अतिक्रमण न हो।